'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 अक्टूबर, 2014

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी–22, अतुल ग्रोव रोड, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001, फोन : 23354841–42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 17 ● अंक 22 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 अक्टूबर, 2014

स्वच्छ मानसिकता से स्वच्छ भारत

डॉ. उदित राज

भारत स्वच्छ अभियान न केवल भौतिक गंदगी की सफाई करेगा बल्कि इसका असर मानसिकता पर भी पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूं कि यह न ही उनके पद के वजह से बल्कि व्यक्तित्व के वजह से राजा हो या फकीर सबके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। सरकारी प्रयास क्या पर्याप्त होंगे कि सन् 2019 तक भारत स्वच्छ हो जाएगा। लगता है इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रयास करने पड़ेंगे तभी जाकर के यह लक्ष्य पूरा होगा। दुनिया के दूसरे देशों में जब हम जाते हैं तब इतनी ग्लानि होती है कि काश हमारा भी देश ऐसा ही साफ–सुथरा होता। सरकार के द्वारा किए गए तरीके भी बड़े ही प्रभावशाली है जैसे कि प्रमुख लोगों को नौ प्रभावशाली लोगों की टीम में खड़ा करना। वे वो लोग हैं जो स्वच्छ भारत देखने की लालसा रखते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अब इनके करने से भी धरातल पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा।

किसने शुरू किया और कब शुरू हुआ, इस पर चर्चा करना बुद्धिमानी नहीं होगी लेकिन सच्चाई यह है कि इस कार्य को एक विशेष जाति के लोग पुश्तैनी कार्य के रूप में कर रहे हैं। अन्य जातियों ने सोचा कि उनका गंदगी करना कार्य है क्योंकि साफ करने वाली जाति समाज में बनी हुयी है। यह प्रवृत्ति शहरों में ज्यादा रही। माना कि गांव में गंदगी को साफ कराने का इंतजार किसी से न हो फिर भी स्वच्छता वहां भी नहीं है। सरकार की उद्घोषणा से कोई गली–कूची देश में नहीं बचा होगा जहां इसकी चर्चा नहीं हुयी हो भले ही सफाई अभियान न हुआ हो। इससे निश्चित तौर से मन में बदलाव आ रहा है और इसी के साथ यह नारा दे देना उचित होगा कि ''क्लीन मेंटेलिटी एंड क्लीन लोकेलिटी'', इसका आशय यह है कि मानसिकता में परिवर्तन लाओ और गंदगी को भगाओ। इससे सांस्कृतिक परिवर्तन होगा जो चिर स्थायी होगा और धीरे–धीरे हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग बन जाएगा। जिस तरह से हम अपना निजी शरीर और घर साफ करते हैं उसी तरह से अन्य जगह भी सफाई रखने की एक मानसिकता बन जाएगी। इस अभियान को व्यवहारिकता में लाने के लिए कविता, उपन्यास, कहानी, पाठ्यक्रम, पत्रकारिता आदि सभी में लिखने, पढ़ने ओर पढ़ाने का भी कार्य करना होगा। बड़ी–बड़ी चर्चायें भी आयोजित की जानी चाहिए। जो अधिकारी, नेता, व्यक्ति, व्यवसायिक प्रतिष्ठान या कोई भी हो जो स्वच्छता रखता हो उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कर्मचारियों–अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके कांफिडेंशियल रिपोर्ट में इसके लिए अंक देने का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी चुनाव में भाग लेने वाले जन प्रतिनिधि के लिए अनिवार्य हो कि वह इस क्षेत्र में कार्य किया हो और उसके आस–पास का वातावरण स्वच्छ हो। सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी जाए चाहे कोटा परमिट, राशन कार्ड इत्यादि, स्वच्छता की शर्त जोड़ देना चाहिए। यह भी देखें कि जिस तरह से अपने सगे–संबंधियों के तमाम हितों की देखभाल करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं तो यह भी देखें कि वे भी स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं।

भारत की स्वच्छता से इतने लाभ होंगे कि इनकी गिनती करना मुश्किल होगा। इस समय भारत की आर्थिक उन्नति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाए, उसके लिए स्वच्छता जरूरी है। विदेशी भारत की गंदगी से बहुत ही कतराते हैं और भले ही मुंह पर न बोले लेकिन पीठ पीछे इसकी चर्चा करते ही हैं। प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर को कहा कि यदि भारत स्वच्छ होता है तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार, प्रति व्यक्ति वर्ष में साढ़े छः हजार का इसलिए बचत करेगा कि जो गंदगी के कारण बीमारी पर खर्च होता है, वो नहीं होगा। भारत का इतिहास है और इसकी अपनी पुरानी संस्कृति है और विदेशी पर्यटक भारत तो आना चाहते हैं लेकिन गंदगी के वजह से नहीं आ पाते। सिंगापूर, थाइलैंड जैसे देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन के वजह से चल रही है लेकिन हमारे यहां दिन प्रति दिन पर्यटक कम ही होते जा रहे हैं। जो हजारों वर्षो से हो न सका, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम से श्रम की महत्ता जो जुबानखर्ची बनी हुयी थी उसे धरातल पर उतार जाएंगे।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयासों द्वारा यह जरूर पैदा कर दें कि जो अभी तक अवधारणाएं थी कि सफाई न करना सम्मान का प्रतीक था, अब पहिया उल्टा घूम जाना चाहिए। चाहे जितना बड़ा हो अगर वह किसी तरह की गंदगी करता है तो उसको समाज में नीचा दर्जा मिलना चाहिए। एक तरफ प्रोत्साहन दिया जाए तो दूसरी तरफ कुछ न कुछ सामाजिक प्रताड़ना भी दिया जाए। जहां पर साफ–सफाई नहीं है वहां पर विकास इत्यादि से भी हाथ खींचने जैसे प्रावधान हो ताकि लोग स्वच्छता की दिशा में सक्रिय रहे। तमाम सारे अनगिनत प्रोत्साहन एवं प्रताड़ना के तरीके हैं कि इस अभियान को कामयाब बनाने से कोई रोक नहीं सकता।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ का सम्मेलन संपन्न

डॉ. अनिल कुमार

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 04–05 अक्टूबर, 2014, स्थान डॉ. अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉ. उदित राज ने कहा कि दलित समाज को जितने भी अभी तक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, वे सामाजिक आंदोलनों से ही संभव हुए हैं। इस देश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उनका इरादा कभी भी चेतन एवं अचेतन अवस्था में दलितों के उत्थान का नहीं रहा। जो जातियां सामाजिक आंदोलन के द्वारा सरकार पर दबाव बना लेती हैं, वे अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहती हैं। डॉ0 अम्बेडकर ने दलित समाज के विकास और अधिकारों के लिए हमें दो तरह के प्रतिनिधि दिए थे। पहले, ऐसे प्रतिनिधि जो चुनकर संसद, विधान सभा एवं स्थानीय निकायों में जाते हैं, दूसरे, सरकारी नौकरियों में आरक्षण का सहारा लेकर समाज के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। हम यह मानते हैं कि सफाई पेशे से जुड़ी जातियों के प्रतिनिधि संसद, विधान सभा एवं स्थानीय निकायों में न के बराबर पहुंचते हैं, इसलिए दलितों का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है लेकिन जो हमारे दूसरे प्रतिनिधि सरकारी नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण का सहारा लेकर प्रवेश करते हैं, उन्होंने बहुत ईमानदारी से समाज–निर्माण का कार्य नहीं किया। सांसद और विधायक केवल पांच साल के लिए विभिन्न पार्टियों के आकाओं की कृपा से टिकट पाकर चुने जाते हैं, उनसे समाज उत्थान के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद करना निरर्थक है, लेकिन जो आरक्षण के सहारे से हमारे अधिकारी 60 साल तक की उम्र के लिए चुनकर जाते हैं, उन्हें तो बाबा साहेब के सपने को साकार करने के लिए कार्य करना चाहिए था, जो अब तक नहीं हो पाया है। बाबा साहेब ने कहा है कि किसी भी समाज को दिशा देने का कार्य उस समाज के पढ़े–लिखे व्यक्ति एवं समाज सुधारक ही कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि इस समाज के शिक्षित, समाज सुधारक एवं सफाई कामगार नेता आपस में वैचारिक तालमेल बिठाकर एवं एकजुट होकर डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को अपनाते हुए समाज की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में सुनिश्चित कराने के लिए संघर्ष करें एवं राष्ट्रीय दलित

शेष पृष्ठ 5 पर ...

उत्तराखंड परिसंघ की बैठक संपन्न

नारायण राम

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के उत्तराखण्ड की कार्यकारिणी ने दिनांक 12 अक्टूबर 2014 को प्रदेश स्तर की बैठक देहरादून के पंचायत हाल में परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं दिल्ली से सांसद डॉ. उदित राज की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। बैठक में उपस्थित लोगों में इतना जोश था कि डॉ. उदित राज के मीटिंग हाल में पहुंचते ही बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीप प्रज्वलित करने के उपरांत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डॉ. उदित राज के स्वागत में उन्हें फूल मालायें पहनाई गयी एवं ढेरों गुलदस्ते भेंट किये गये। हाल में उपस्थित प्रत्येक सदस्य डॉ. उदित राज को फूलमाला पहनाना चाहते थे एवं उनके नजदीक जाना चाहते थे। डॉ. उदित राज ने भी किसी को निराश नहीं किया और उन्होंने प्रदेश व बाहर से आये प्रतिनिधियों से माला ग्रहण कर सभी का हाल-चाल पूछा।

डॉ. उदित राज ने परिसंघ के पदाधिकारियों एवं हाल में उपस्थित सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हुये कहा कि परिसंघ के कार्यकर्ता भारतवर्ष के छोटे गांव में भी परिसंघ की गतिविधियों से समाज को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने परिसंघ के द्वारा फैलाई जा रही विचार क्रांति का जिक्र करते हुये कहा कि यह परिसंघ का ही करिश्मा रहा कि इसने भारतवर्ष की सबसे बड़ी रैली की, उनके द्वारा ही देश हित में बहुजन लोकपाल बिल पेश किया गया जिसके आधार पर लोकपाल के पद पर आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। वर्ष 2006 में जब सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण का मामला चल रहा था तो बिना किसी साधन व लोगों के सहयोग के अकेले सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण के पक्ष में पैरवी करवाई व सरकार से वकील की फीस 40 लाख रुपए दिलवाकर आरक्षण को बचाया। सुश्री मायावती की सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को अच्छी तरह से डिफेंड नहीं किया गया। न्यायाधीश तीनों बातों को मान रहे थे परन्तु इसका जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण पदोन्नति में आरक्षण से वंचित होना पड़ा। परिसंघ ने जिस आरक्षण को संसद व न्यायालय से बचाया वही आरक्षण मायावती की सरकार रहते हुये लखनऊ में छिन गया।

डॉ. उदित राज ने दुःख जताते हुये कहा कि परिसंघ के पदाधिकारी संगठन का उपयोग अपने काम व अपनी पहचान बनाने के लिये कर रहे हैं, समाज के हित के लिये नहीं कर रहे है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का जिक्र करते हुये कहा कि इस मद में अनुसूचित जाति के लोगों को बजट का 15 प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिये था परन्तु मिलता है मात्र 7 या 8 प्रतिशत हिस्सा। ऐसा ही अनुसूचित जन जाति के मामले में भी होता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि समाज कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय के अनुपूरक बजट में पहली बार चर्चा हुई।

डॉ. राज ने यह भी कहा कि वर्तमान दौर मजदूर व मालिक बनने का चल रहा है। यदि जीत गये तो मालिक बनेंगे और हार गये तो मजदूर बनना पड़ेगा। आज अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग किसी भी क्षेत्र में मालिक नहीं हैं, चाहे यह उद्योग धन्धे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, होटल व्यवसाय हो या ट्रांसपोर्टेशन हो। यदि मालिक नहीं बनेंगे तो पेट नहीं भरेगा। जो पेट भरने लायक नहीं बनते, वे मान-सम्मान की बातें नहीं करते। मान-सम्मान की बात वही करता है जिसका पेट भरा होता है। यदि अधिकार नहीं होगा तो विचार भी नहीं होगा। परिसंघ आपको सम्मान दिलाने के लिये कुछ नहीं मांगता है केवल पूरे वर्ष में दो दिवस का समय व दो दिवस का वेतन आपके अधिकारों की रक्षा के लिये मांगता है। आजादी के 60 साल बाद भी अनुसूचित जाति के अधिकतर लोग भूमिहीन हैं इन्हें भूमि की अत्यन्त आवश्यकता है। परिसंघ का संघर्ष तक तक जारी रहेगा जब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण, सीधी भर्ती व पदोन्नति में आरक्षण व आरक्षण का कानून, उच्च न्यायपालिका व सेना में आरक्षण का प्रावधान समान व अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं हो जाता है।

उत्तराखण्ड फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मदन शिल्पकार व कार्यकारी अध्यक्ष श्री करम राम ने अपने विचार व्यक्त करते हुये डॉ. उदित राज से निवेदन किया कि उत्तराखण्ड की सरकार अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों का ध्यान नहीं रख रही है। हजारों की संख्या में अस्थाई नियुक्तियां की गयी है परन्तु इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को नियुक्ति नहीं दी गयी है। अनुसूचित जाति के लोगों को एक षड्यंत्र के तहत नियुक्तियों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस विभाग का हवाला देते हुए कहा कि कुछ समय पूर्व पुलिस विभाग में निरीक्षकों को पदोन्नत कर डी0एस0पी0 बनाया गया परन्तु एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को पदोन्नति नहीं दी गयी। यदि आरक्षण का ध्यान रखा गया होता तो लगभग 7 पदों पर अनुसूचित जाति के सदस्यों की पदोन्नति होती। श्री करमराम व श्री मदन शिल्पकार ने माननीय उदित राज से कहा कि आप ही अब हमारे रक्षक बन कर उत्तराखण्ड के लोगों को आरक्षण से वंचित होने से बचायें व मुख्यमंत्री पर दबाव डाल कर हमारे हितों की रक्षा करें। इस सम्बन्ध में उदित राज ने आश्वस्त किया कि अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों की रक्षा के लिये उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया जायेगा। यदि मुख्यमंत्री ने जायज मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया तो राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाया जायेगा। कुमाऊं मण्डल के अध्यक्ष नारायण राम ने अपनी बात रखते हुये सभी से परिसंघ को सहयोग देने को कहा ताकि परिसंघ की ताकत का फायदा निर्बल वर्ग के लोगों को मिलता रहे। सामाजिक कार्यकर्ता श्री मेहर सिह ने मीडिया पर निशाना साधते हुये कहा कि मीडिया निर्बल वर्ग के प्रति भेदभाव रखता है। निर्बल वर्ग के हितों के तथ्यों की अनदेखी करता है। उन्होंने इसके कई उदाहरण दिये। सभा को श्री बलबीर सिह, श्री सत्येन्द्र प्रियश्री, श्री विक्रम सिंह, श्री केदारनाथ, श्री पुष्कर राम, श्री केदार नाथ, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह आदि ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता श्री हीरालाल व संचालन श्री रोहित कुमार ने किया। सभा का समापन करते हुये श्री हीरा लाल ने सभी उपस्थित सदस्यों व मीडिया का धन्यवाद किया।

राष्ट्रीय स्तर पर डाइवर्सिटी आंदोलन की तैयारी

नई दिल्ली। बहुजन डाइवर्सिटी मिशन निजी क्षेत्र में दलित वर्गो की भागीदारी को लेकर देशव्यापी मुहिम चलाने की तैयारी में जुट गया है। मिशन के अध्यक्ष एच. एल. दुसाध ने 'भारतीय सामाजिक संस्थान' में आयोजित नौवें डाइवर्सिटी डे के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को आह्वान किया कि वह निजी क्षेत्र में डाइवर्सिटी के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी मोर्चा बनाने की दिशा में प्रयास करे, क्योंकि मौजूदा सरकारें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक आरक्षण को महज कागजों तक सिमटा देना चाहती है।

दलित चितंक व विचारक डॉ. महेन्द्र प्रताप राना ने कहा कि आज अनुसूचित जाति और जनजातियों से क्रमशः 84 व 47 अर्थात् 131 संसद सदस्य चुन कर आते है। विभिन्न पार्टियों की विचारधारा से बंधे यह सांसद अपने समुदायों के मुद्दों को ठोस तरीके से रखने में भी कतराते है। उन्होंने कहा कि यह सांसद संविधान की धारा 330, 332 व 334 के तहत जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं अतः इन वर्गो से आने वाले सांसदों को पार्टी के बंधन से अलग मान्यता मिलनी चाहिए तभी इन वर्गो के मुद्दें सही स्थान पा सकेगें।

दैनिक स्वराज खबर के संपादक विजयेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि दलित वर्गो को पिछली कई शताब्दियों से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पीछे धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं और डाइवर्सिटी से ही वह अपने अधिकारों को पा सकेगें।

दलित ईसाई नेता एवं स्तंभकार आर. एल. फ्रांसिस ने कहा कि भू मंडलीकरण के कारण निजी क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज के समय दलित-आदिवासी आरक्षित मुठ्ठीभर सरकारी नौकरियों के सहारे आगे नही बढ़ सकते। डाइवर्सिटी उनके जीवन की जरुरत बन गई है। निजी क्षेत्र में डाइवर्सिटी की मांग करते समय इसमें सामाजिक क्षेत्र को भी शामिल किया जाना चाहिए। आर. एल. फ्रांसिस ने कहा कि भारत का चर्च संसाधनों के हिसाब से शक्तिशाली संयुक्त संस्थान है जो बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाता है। पिछले कई दशकों से चर्च राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दलित और आदिवासी समूहों के अधिकारों की आवाज उठा रहा है। दलित संगठनों को अब चर्च से भी मांग करनी चाहिए कि वह मानवीय आधार पर अपने संस्थानों में इन वर्गो के लिए डाइवर्सिटी लागू करे।

भाजपा सांसद डा. उदित राज ने डाइवर्सिटी मिशन को आम दलितों के बीच ले जाने और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर बल दिया। कर्यक्रम को प्रोफेसर हेमलता महेश्वरी, डा. कौशिश, शिव बौधी, श्री सुरेश ने सम्बोधित किया।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

आगामी रैली से संबंधित हैंडबिल का नमूना छापा जा रहा है। परिसंघ के नेताओं से अपील है कि अपनी ओर से भी छपवाकर वितरित करें व तैयारी जोर - शोर से करें

परिसंघ के आवाहन पर

अधिकार एवं सम्मान प्राप्त

रैली

डॉ० उदित राज (संसद, लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे लाखों की संख्या में रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर एकत्रित हों

18/10/2014

प्रिय साथियों,

अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ अक्टूबर, 1997 में आरक्षण विरोधी आदेशों की वापसी के लिए अस्तित्व में आया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 तथा 29/08/1997 के आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए गए थे। हमारे आंदोलन के दबाव में आकर संसद ने संविधान में 81वां, 82वां एवं 85वां संशोधन किया जिसके कारण आरक्षण बच सका।

निजीकरण एवं भूमंडलीकरण के कारण जिस तरह का विकास इस देश में हो रहा है उससे समाज दो वर्ग में बंटता जा रहा है एक है मालिक और दूसरा श्रमिक। जिनका उत्पादन शक्तियों पर कब्जा नहीं है, वे इस दौर में मजदूर के अलावा और कुछ नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि दलितों, आदिवासियों एवं पिछड़ों के हाथ में उत्पादन शक्तियों पर कोई मालिकाना हक नहीं है। गत् कई वर्षों से अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करता आ रहा है लेकिन यूपीए की सरकार ने समितियां तो तीन-तीन बनायी लेकिन देश की पूंजीपति संगठनों ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉंसिबिलिटी के नाम पर मामले को रफा-दफा करके इस अधिकार से वंचित रखा है। इस अधिकार का न मिलने का दूसरा कारण यह रहा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के हजारों संगठन और नेता गलतफहमी में या इरादतन समाज के संसाधनों का दुरूपयोग करते रहे हैं और कहते हैं कि लड़ाई समाज की है लेकिन वास्तव में वह अपने संगठन को बचाने के लिए शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। संगठन बचेगा तभी उनकी नेतागिरी जिंदा रहेगी। दलित समाज के भोले-भाले लोग इसे मिशन समझ लिये लेकिन परिसंघ ने कभी संगठन बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि वह आंदोलन के रूप में ढ़ल गया था और पूरी ताकत से अधिकार के लिए संघर्ष किया लेकिन समाज का सहयोग नहीं मिल सका इसलिए अभी तक ये उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए। परिसंघ गैर राजनीतिक संगठन है और इसके मंच पर साल में एक बार दिल्ली में इकट्ठा होने की ही अपील होती रही है। परिसंघ के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वे तो पूर्णकालिक रूप से लगे रहते ही हैं। समाज से अपील है कि राजनीतिक एवं अपने सामाजिक संगठनों से ऊपर उठकर अधिकार प्राप्ति के लिए वर्ष में एक दिन का समय दे दें तो भी हम लड़ाई जीत जाएंगे। क्या एक दिन का समय और एक दिन का वेतन मांगना बहुत ज्यादा है ? लोग केवल एक दिन लाखों की संख्या में दिल्ली में आकर खड़े हो जाएं तो भी राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बन जाएगा तो हमारी मांगे जैसे : आरक्षण कानून बनवाना, पदोन्नति में आरक्षण का विधेयक संसद में पास कराना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, को मजबूत करने के लिए संसद में लंबित बिल, स्पेशल कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान को आबादी के अनुपात में बजट आवंटन को कानूनी मान्यता, एक राज्य में बना जाति प्रमाण पत्र दूसरे राज्य में मान्य होना, सफाई के काम में ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, समयबद्ध पदोन्नति, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति, समान शिक्षा एवं सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/ जन जाति संगठनों की मान्यता जैसे अधिकारों को पूरा कराना बिल्कुल संभव हो जाएगा।

यक्ष प्रश्न यह है कि परिसंघ के ही बैनर के नीचे लोग क्यों जमा हों ? जवाब है कि 1997 से लेकर अब तक किसी संगठन ने एक अधिकार भी समाज को नहीं दिलाया है। जिस दिन परिसंघ नकारा हो जाए, समर्थन मत देना। संवैधानिक संशोधन तो करवाया ही उसके बाद जितने भी अधिकार जोड़े गए चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना और जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए 2001 में एक विशाल दीक्षा, 2006 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण में पैरवी करना, अनुसूचित जाति/जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम को कमजोर करने का यूपी सरकार के प्रयास को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बचाना, पिछड़ों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू कराने की लड़ाई लड़ना, लोकपाल में आरक्षण, आदि। क्या कोई और संगठन इतने अधिकार दिलवा पाया ?

डॉ. उदित राज दलितों-आदिवासियों की आवाज उठाने संसद में भाजपा की ओर से गए हैं और इसके लिए भाजपा का धन्यवाद। हमें इस बात का गर्व है कि डॉ. उदित राज के आहावन पर भागीदारी के लिए लोक सभा के चुनाव में दलितों ने भाजपा को सर्वाधिक वोट दिया। सरकार आते ही सकारात्मक कार्य शुरू हुआ। जो अधिकार जन प्रतिनिधि के द्वारा दिए जाते थे, न्यायपालिका उसे छीनने का कोशिश करती थी लेकिन सरकार ने 121वीं संवैधानिक संशोधन करके राष्ट्रीय न्यायायिक नियुक्ति आयोग जिसमें 6 सदस्य होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या किसी भी जनतांत्रिक देश में जज की भूमिका जज बनाने में नहीं होती लेकिन भारत में ही ऐसा क्यूं ? यह कार्य दस साल में यूपीए सरकार नहीं कर सकी और मोदी जी के सरकार आते ही अच्छे दिन लाने लगी। इसके अतिरिक्त पार्टी ने उदित राज को संसद में सवाल उठाने का मौका दिया जो अभी तक नहीं उठा। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अनुदान बजट पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुयी थी और इस पर बहस डॉ. उदित राज से शुरू हुयी और उन्होंने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत जितना पैसा अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए वह कभी नहीं मिला। कांग्रेस ने ऐसी विरासत छोड़ी कि यह आवंटन कभी 8 प्रतिशत से ज्यादा रहा ही नहीं। 2014-15 के प्लान बजट के तहत कुल 5,75,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस बार भी दलितों के लिए 8.79 प्रतिशत का ही प्रावधान है। यदि अनुसूचित जाति की आबादी 15 प्रतिशत व जन जाति की 7.5 प्रतिशत भी मान ली जाए तो अनुसूचित जाति के लिए 86,250 करोड़ रूपए होना चाहिए था जबकि बजट में 50,548 करोड़ रूपए का ही प्रावधान है। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए 43,125 करोड़ रूपए का प्रावधान होना चाहिए था जबकि 32, 387 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम लाखों की संख्या में इकट्ठा हों तो डॉ. उदित राज को और ताकत मिले और आने वाले दिनों में जो सारे सांसद मिलकर नहीं कर सके हैं वह हो जाए।

फूले-शाहू या सामाजिक न्याय की विचारधारा मानने वाले से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता और यह परिसंघ का अटूट विश्वास है। जब भारत की शासन सत्ता में दलित, आदिवासी एवं पिछड़े नहीं थे तो देश बाहर वालों का गुलाम था और आजादी के बाद सबकी भागीदारी हुयी है चाहे कम हो या ज्यादा, तो क्या किसी की हिम्मत है कि सोच भी सके कि वह भारत को गुलाम बना लेगा ? हम तो किसी भी दृष्टि से जातिवादी नहीं है लेकिन जो वंचित हैं उनके लिए अधिकार मांग करके एक खुशहाल एवं समतामूलक समाज, एकात्म समाज, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के अलावा और हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है ?

भले ही जो लोग डॉ. उदित राज या परिसंघ को न भी मानते हों तो भी समाज के हित के लिए इस अधिकार एवं सम्मान प्राप्ति महा अभियान में 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, अजमेरी गेट, नई दिल्ली में लाखों की संख्या में प्रातः 10 बजे शामिल हों।

निवेदक

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.- 9871237186), नेतराम ठगेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल (दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, आलेख मलिक (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एम. पी. कुमार, एस. करुपैय्या (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प.बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरुषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ
पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1, फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

जय भीम ! जय भारत !!

अनुसूचित जाति / जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय

परिसंघ

के आवाहन पर

डॉ० उदित राज (सांसद, लोक सभा)
राष्ट्रीय चेयरमैन

अधिकार एवं सम्मान प्राप्ति के लिए महारैली

08 दिसंबर, 2014 (सोमवार) को प्रात: 10 बजे रामलीला मैदान, नई दिल्ली पर

निवेदक :

भवननाथ पासवान, जगजीवन प्रसाद, डॉ0 अनिल कुमार, एस. पी. सिंह, धर्म सिंह (उ0प्र0), इंदिरा आठवले, सिद्धार्थ भोजने, प्रकाश पाटिल (महाराष्ट्र), एस. पी. जरावता, महासिंह भूरानिया, मनीराम सरोहा (हरियाणा), तरसेम सिंह, हंसराज हंस, दर्शन सिंह चंदेढ़ (पंजाब), विनोद कुमार (मो.- 9871237186), नेतराम ठगेला, कंवर सिंह, डॉ. नाहर सिंह, एन. डी. राम, रविंद्र सिंह, ब्रह्म प्रकाश, डॉ. धनंजय, डॉ. अंजू काजल, ए. के. लाल (दिल्ली), मूला राम, इन्द्राज सिंह, विश्राम मीना (राजस्थान), हीरा लाल, एच.सी. आर्या, रोहित कुमार, जयपाल सिंह (उत्तराखंड), डी.के. बेहरा, आलेख मलिक (उड़ीसा), परम हंस प्रसाद, बी. भारती, आर. बी. सिंह, पी. के. राय (म.प्र.), आर. एस. मौर्या, एन. जे. परमार (गुजरात), एम. पी. कुमार, एस. करुपैय्या (तमिलनाडु), के. रमनकुट्टी (केरल), मधु चन्द्रा (मणिपुर), महेश्वर राज, जी. शंकर, प्रेम कुमार, आई मैसया, एस. रामकृष्णा, जे. बी. राजू, वाई. एम. विजय कुमार, बी. नरसिंह राव, पी. वी. रमणा (आन्ध्र प्रदेश), अनिल मेश्राम, हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़), कमल कृष्ण मंडल, रामेश्वर राम, सपन हलदर (प. बंगाल), मधुसूदन कुमार, दिनेश कुमार, विनय मुंडू (झारखण्ड), आर. के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर), मदन राम, कुमार धीरेंद्र (बिहार), जे. श्रीनिवासलू, जी. वेंकटस्वामी, पुरूषोत्तम दास (कर्नाटक), सीताराम बंसल (हि.प्र.)

पत्राचार : टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1,
फोन : 23354841-42, टेलीफैक्स : 23354843 Email : dr.uditraj@gmail.com

शेष पृष्ठ 1 का ...

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ का सम्मेलन संपन्न

आंदोलनों में हिस्सा लेकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करें।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि कोई भी समाज जब अपने सम्मान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करता है तो उस समाज को अपने इतिहास की जानकारी का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इतिहास से ही समाज को अपने मान-सम्मान एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा एवं गति मिलती है। यदि दलित जातियों के इतिहास पर नजर डाली जाए तो ये पूर्व में भारतवर्ष की मूल निवासी एवं शासक जातियां रही है। इनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी पहचान थी। मध्य एशिया से चलकर आर्यो ने भारत आकर अपनी राजसत्ता एवं धर्मसत्ता स्थापित करने का षड्यंत्र रचा। अपनी-अपनी धर्मसत्ता एवं राजसत्ता के लिए भारत के मूल निवासी एवं आर्यो के बीच संघर्ष हुआ जिसमें आर्यो ने छल, बल एवं कपट के द्वारा यहां के मूल निवासियों को इनकी राजसत्ता एवं धर्मसत्ता से बदखल करके अपनी सत्ता स्थापित की। और समाज को संचालित करने के लिए चार वर्णो में विभाजित किया जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां के मूल निवासी जातियों को विभिन्न उपजातियों में बांटकर घृणित एवं निम्न कार्य करने के लिए बाध्य किया। कालांतर में ये जातियां अपनी सामाजिक एवं आर्थिक दुर्दशा को भाग्य एवं भगवान की देन मानने लगी और लगातार पिछड़ती गयी और दलित जातियों के नाम से जानी जाने लगीं।

विनोद कुमार ने आगे कहा कि दलित जातियों में कई-कई उपजातियां जैसे चमार, धोबी, खटिक, कोली, धानुक इत्यादि है। इनमें एक सफाई पेशे से जुड़ी जाति भी है जैसे-बाल्मीकि, मेहतर, डोम, चांडाल, हेला, चूहड़ा, एवं भंगी इत्यादि। इनके उत्थान के लिए बहुत से महापुरुषों ने संघर्ष किया, सूफी जागरण किए लेकिन इनकी सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हो सका। भारत की जातिवादी व्यवस्था के कारण यह देश मुस्लिम एवं अंग्रेजों का गुलाम रहा लेकिन इनके शासनकाल में भी इनकी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया और इनका जीवन बद से बदतर होता चला गया। जब देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था तो देश की आजादी एवं इन जातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी एवं एम. आर. जेकर ने प्रयास किया और गांधीजी हरिजन बस्ती पंचकुईयां, नई दिल्ली में इनके बीच में जाकर रहे और सफाई का कार्य कुछ दिनों के लिए किया। इस प्रकार गांधीजी ने सफाई कार्य को महान कार्य बताया। इस कार्य को महान बताकर एवं देश को आजादी दिलाने के पश्चात् गांधीजी राष्ट्र पिता कहलाये। लेकिन जो जातियां हजारों वर्षो से सफाई के कार्य को करती आ रही है, वे क्या मान-सम्मान एवं अधिकार प्राप्त कर पायीं ?

डॉ. बी. आर अंबेडकर एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने दलित होने के वजह से यहां की विषमतावादी समाज में जो अपमान झेला, उससे आहत होकर विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में शिक्षित एवं सक्षम होकर भारत की एकता एवं जातिविहीन समाज की स्थापना के लिए संपूर्ण दलित समाज के सम्मान एवं अधिकार के लिए संघर्ष करके शिक्षा, सरकारी नौकरियां एवं राजनैतिक क्षेत्र में आरक्षण का संवैधानिक अधिकार प्राप्त किया। जिसकी वजह से दलित समाज में कुछ जातियों ने प्रगति की। डॉ. बी. आर. अंबेडकर की विचारधारा, पेशा परिवर्तन, शिक्षा ग्रहण करना, संगठित रहना एवं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आदि को जिन दलित समाज के व्यक्ति या उपजातियों ने अपनाया, वे व्यक्ति या उपजातियां विकास की मुख्यधारा से जुड़कर मान-सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सफाई पेशे से जुड़ी जातियां जाने-अनजाने में भाग्य, भगवान एवं इस देश की विषमतावादी व्यवस्था में विश्वास करती रही और डॉ. अंबेडकर एवं दलित महापुरुषों के रास्ते पर न चलकर गांधीजी के बताये हुए रास्ते पर चलती रही। जिसके परिणामस्वरूप ज्यादातर लोग इन जातियों में से शिक्षा, मान-सम्मान और देश की मुख्यधारा में शामिल होने से वंचित रहे।

उन्होंने सफाई पेशे संबंधी कार्यों पर विस्तृत रूप से अपनी भावी योजना के बारे में मौजूद लोगों को बताया कि सफाई पेशे से जुड़ी जातियों में ज्यादातर लोगों का मुख्य पेशा केंद्रीय, प्रदेश एवं अर्धसरकारी विभागों, नगरपालिका और गांव-कस्बों में सफाई का कार्य करना है। अब यह कार्य सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से ठेकेदारी प्रथा में जा चुका है जिससे इस समाज का जीवन बद से बदतर होता जा रहा है और इसको रोकने के लिए भारत में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर के विभिन्न संगठन कार्यरत हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है या आंशिक रूप में मिल रही है जिसका लाभ न के बराबर है। इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो उनके आंदोलन की दिशा गलत है या फिर केवल आत्मिक संतुष्टि हेतु कार्यरत हैं। पूरी दुनिया में वही आंदोलन सफल हुए हैं जिनके अंदर एक विचारधारा एवं अधिकारों के लिए संघर्ष करने की ज्वलंत इच्छाशक्ति होती है। ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति निकायों/दफ्तरों पर धरना-प्रदर्शन करने से नहीं होगी। यह राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे पूरे देश से लोगों को संगठित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा एवं लाखों-लाख की संख्या में एकत्रित होकर ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, समयबद्ध पदोन्नति, सफाई के कार्य में नियमितिकरण का समय-सीमा का निर्धारण, महिलाकर्मियों के सेवा समय में परिवर्तन जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षित एवं सेवा निर्वाह कर सके एवं चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस कार्ड आदि के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार का ध्यान इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए आकर्षित कराना होगा।

विनोद कुमार ने आगे बताया कि 2 अक्टूबर, 2014 को भारत के नेताओं, नौकरशाहों एवं प्रगतिशील विचारधारा के लोगों ने सफाई कार्य को महान मानकर झाड़ू को बड़े प्यार से अपनाया है लेकिन क्या वे सब लोग सफाई पेश से जुड़े लोगों को दिल से अपना पायेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश को स्वच्छ रखने एवं महात्मा गांधी के हरिजन जाति को मान-सम्मान दिलाने के सपने को पूरा करने की शुरुआत की है, जो स्वागत योग्य है। आदरणीय मोदी जी ने अपने संबोधन में 2019 तक जो स्वच्छ भारत का सपना महात्मा गांधी का था को पूरा करने का संकल्प लिया। अब यह देखना है कि 2019 तक, सफाई पेशे से जुड़ी जातियां जो हजारों वर्षो से इस देश को महामारी एवं भयंकर बीमारियों से देश की गंदगी साफ करके बचाती आ रही है, उन जातियों को इन पांच सालों में जो कांग्रेस की सरकार जो पिछले कई दशकों में उन्हें मान-सम्मान, शिक्षा, जीवन-यापन के साधन देने में नाकाम रही, क्या मोदी नेतृत्व वाली सरकार इसे दे पाने में सफल रहेगी? डॉ. अंबेडकर पैतृक पेशा परिवर्तन के आधार पर भारत को जातिविहीन व समतामूलक समाज बनाना चाहते थे जिससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। 2 अक्टूबर, 2014 को सफाई पेशे से जुड़ी जातियां कहीं सफाई के पेशे को अपना पैतृक पेशा एवं महान कार्य मानकर विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना न बंद कर दें। जिसका परिणाम इनका विकास तो अवरुद्ध होगा ही साथ ही साथ देश भी विकास के रास्ते से वंचित न हो जाये।

उन्होंने आगे कहा कि हम आदरणीय मोदी जी से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए उनके जन्म दिवस 2 अक्टूबर को क्रांतिकारी कदम उठाया है ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब के जन्म दिवस 14 अप्रैल को असमानता, छुआछूत एवं जातिविहीन समाज के सपने को पूरा करने के लिए मोदी जी राष्ट्रव्यापी आंदोलनकारी कदम उठाएंगे जिससे डॉ. अंबेडकर एवं उनके माननेवालों का सपना पूरा होगा।

सफाई कामगार संगठनों का परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज एवं विभिन्न प्रदेशों के दलित नेताओं के नेतृत्व में भागीदारी, पदोन्नति में आरक्षण, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति, संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमित करने एवं सफाई कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति के लिए 8 दिसंबर, 2014 को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में महारैली होनी है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव श्री राम लाल, एमसीडी स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन श्री मोहन प्रसाद भारद्वाज एवं मेयर श्रीमती मीनाक्षी सूर्यवंशी ने सफाई कर्मचारियों की समस्या को हल करने के लिए आश्वासन दिया।

इस मौके पर अशोक अंजाना, परमेंद्र, अजय कुमार उर्फ रिंकू खेड़ा, राजेश खेड़ी, अमर पाल गहलोत, देव कुमार, हेमंत, जे. पी. टांक, वेद प्रकाश बिडलान, महेंद्र सिंह राठी, सतनारायण, जितेंद्र, सुनहरी लाल, बिरजू पहलवान, विकास बाल्मीकि, श्रीमती संतोष एवं विभिन्न प्रदेशो से आए प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार रखें।

Reg. No.33084/98/New Delhi (ALL INDIA CONFEDERATIN OF S.C./S.T.ORGANISATIONS Affiliated)

CENTRAL OFFICE

NSOSYF

NATIONAL SC,ST,OBC STUDENT & YOUTH FRONT

Opening On 8 Oct. 2014 Time : 11.00 am

Room No.07, Vitthal Bhai Patel House, Patel Chowk Metro, New Dehli- 1

Chief Patron

Dr. Udit Raj (Ex. IRS.)

Member of Parliament

D. Harshavradhan

National Co-ordinator

0 7709975562

Jai Bheem !

Jai Bharat !!

All India Confederation of SC/ST Organisations

Dr. Udit Raj (M.P, Lok Sabha)
National Chairman

Call

For Dignity & Rights

MAHARALLY

at

Ramleela Maidan, New Delhi on 08th Dec., 2014 (Monday) at 10 AM

By

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S. P Singh, Dharm Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Netram Thagela, Kanwar Singh, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D. K. Behera, Aalekh Malik (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), M. P. Kumar, S. Karuppaiah (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar, Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1,
Tel : 23354841-42, Email : dr.uditraj@gmail.com

Sample of the Handbill for the forthcomming Rally is being published. It is an earnest appeal to the Confederation Leaders that they should get it printed and distributed

Confederation Call For A Rally For Dignity & Rights

Dr. Udit Raj (M.P, Lok Sabha)
National Chairman

On 08th December, 2014 (Monday) at 10 AM, Lakhs of People to Assemble at Ramleela Maidan, New Delhi.

18/10/2014

Dear friends,

The All India Confederation of SC/ST Organizations came into being in October 1997 to cancel anti-reservation orders dated 30/01/1997, 02/07/1997, 22/07/1997, 13/08/1997 and 29/08/1997 issued by the Department of Personnel & Training, Government of India. Due to our vibrant struggle, the Government made 81st, 82nd and 85th amendments in the Constitution of India and the reservations were protected.

Privatization and globalization have divided the world in two classes – the rich and the poor. Those who do not own means of production will be reduced to labourers. It is very much evident that the Dalits and Adivasis do not own means of production. For the past many years the All India Confederation has been demanding reservation in private sectors but the UPA Government got away with the excuse of making three committees which yielded nothing except an eye-wash under the pretext of 'corporate social responsibility'. Lack of consciousness and existence of multiple organizations came in the way of unity to muster enough support to build the pressure on the Government. These organizations, deliberately or innocently, have been misusing the resources, time and talent under the notion that they are carrying forward the caravan of Baba Saheb Dr. Ambedkar. In fact, most of them have exhausted their energy in protecting their own organization rather than pressurizing the Government to accede to their demands. Why did they waste their energy to protect their own organization, had their vested interests to save their own leadership as office-bearers not been there? So all their efforts were finished before reaching the target and in such a situation, they sometimes harmed the society more than whatever little they could serve it. The innocent Dalits mistook it as a mission and the Confederation never passed through such phase because it got culminated into a nationwide movement just after its making under the visionary leadership of Dr. Udit Raj. Under these circumstances, our goals are still unachieved. We would like to clarify once again that our Confederation is non-aligned to any political party and we appeal to all concerned to come to Delhi to join us on 8th of December 2014 at 10 a.m. at Ram Lila Maidan, Delhi Gate. All are requested to join their hands with us and we are sure to win. One day's time or one day's salary is not a big demand for such a big cause. If lakhs of people come to Delhi to render their support, it will have a great bearing on the Government and the demands like reservation in promotions, redressal of SC/ST grievances, passing of Bill to strengthen the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989, allocation of budget under Special Component Plan and Tribal Sub Plan as per population ratio, recognition of caste certificate of one State in other State, ban on contract system in Safai work and regularizing them and their time-bound promotion, equal education for all and recognition to SC/ST organizations by Government departments. All these rights would become a reality if we all fight unitedly.

The main question arises as to why we should all unite under the banner of Confederation. The answer is that since 1997 not any other organization has achieved even a single right. If we become like any other organization that do nothing, we will not ask for any support and will end up all activities. We have already fought relentlessly for reservation in private sectors, reservation in promotions in the Supreme Court of India in 2006, successfully defended the dilution of SC/ST Atrocities Act by the UP Government in Allahabad High Court, reservation in higher education for OBCs, reservation in Lok Pal, etc., etc. Did any other organization fight for and achieve so many rights for SC/STs and OBCs?

Dr. Udit Raj has reached to the Parliament to raise the voice of weaker section. We thank you and the BJP for this. It was on the call given by Dr. Udit Raj that SC/STs supported BJP in a big way in Lok Sabha elections. The BJP Government has started good beginning by making 21st Constitutional Amendment to make National Judicial Appointments Commission. What is happening is that the rights which we get from people's representatives are being diluted by judiciary. Now the judges will be selected by the Commission comprising six members and one of them will be from SC/ST/OBC. Now there is a chance to get the fairer deal. In no advanced countries like America, England, Germany, Russia or any democratic nation, the judiciary has role to play in their own appointments. Why this practice in India? The UPA Government could not do this job in ten years but the Modi ji made it possible to bring 'good days'. Besides, the party gave the opportunity to Dr. Udit Raj to raise the issues in the Parliament. There had never been any discussion in the Parliament on the Ministry of Social Justice & Empowerment while passing the demand for grant since Independent. Dr. Udit Raj raised the issue of budget allocation for SCs/STs according to their population. In the budget Rs. 50,548 core is allocated but it should have been Rs. 86,250 crore. For STs the allocation was Rs. 32,387 core whereas as per Tribal Sub Plan it should be Rs. 43,125 crore. This exploitative policy was pursued by the Congress Government. If we could muster support in lakhs under the leadership of Dr. Udit Raj, we will certainly gain dignity and right which other members of Parliament could not do.

The Confederation believes that we are true nationalist and our efforts automatically culminate in strengthening the unity and integrity of India. Thus, believers in social justice are the purest nationalists. Please do not forget the fact that India spent hundreds of years in slavery and insubordination of the foreigners when there was no participation of different communities and castes in the governance of the country. The SCs/STs and OBCs got an opportunity to participate in the governance of the country after Independence and nobody can now think of colonizing it. We are not casteists from any angle. But we are fighting for the rights of the people who are deprived of their rights for centuries. Our main aim is to build a society which can achieve a strong and happy nation. Even those who do not accept the leadership of Dr. Udit Raj and are the part of the Confederation, they should also participate in large numbers for the cause. The cause is supreme. Please join the Rally in lakhs at Ram Lila Maidan, Delhi Gate at 10 a.m. on 8th December, 2014.

By

Bhawan Nath Paswan, Jagjivan Prasad, Dr. Anil Kumar, S.P Singh, Dharm Singh (UP), Indira Athawale, Siddharth Bhojne, Prakash Patil (M.S.), S.P. Jaravta, Maha Singh Bhurania, Maniram Saroha (Haryana), Tarsem Singh, Hansraj Hans, Darshan Singh Chanded (Punjab), Vinod Kumar (M.- 9871237186), Netram Thagela, Kanwar Sen, Dr. Nahar Singh, N. D. Ram, Ravinder Singh, Brahm Prakash, Dr. Dhananjay, Dr. Anju Kajal, A. K. Lal (Delhi), Moola Ram, Indraj Singh, Vishram Meena (Rajasthan), Hira Lal, H.C. Arya, Rohit Kumar, Jaipal Singh (U.K.), D. K. Behera, Aalekh Malik (Orissa), Param Hans Prasad, B. Bharti, R. B. Singh, P. K. Roy (M.P.), R.S. Maurya, N. J. Parmar (Gujarat), M. P. Kumar, S. Karuppaiah (T.N.), K. Raman Kutty (Kerala), Madhu Chandra (Manipur), Maheshwar Raj, G. Shankar, Prem Kumar, I Mysaiah, S. Ramkrishna, J. B. Raju, Y. M. Vijay Kumar, B. Narsingh Rao, P. V. Ramna (A.P.), Anil Meshram, Harsh Meshram (Chattisgarh), Kamal Krishna Mandal, Rameshwar Ram, Sapan Haldar (W. Bengal), Madhusudan Kumar, Dinesh Kumar, Vinay Mundu (Jharkhand), R.K. Kalsotra (J&K), Madan Ram, Kumar, Dhirendra (Bihar), J. Shriniwaslu, G. Venkatswamy, Purushottam Das (Karnataka), Seetaram Bansal (H.P.).

All India Confederation of SC/ST Organisations

Corres.: T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-1, Tel : 23354841-42, Telefax: 23354843, Email : dr.uditraj@gmail.com

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 17 ● Issue 22 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 October, 2014

Colossal Resolution Passed by the Chennai Conference

M. P. Kumar

Chennai: The State Conference of All India Confederation of SC/ST Organizations was held at Chennai. Its National Chairman and Member of Parliament, Dr. Udit Raj, former IRS, participated in the Conference as one of the chief guests. Mr. S. Karupaiah, State General Secretary welcomed the gathering and Mr. M. P. Kumar, President, presided over the function. The following mammoth resolution was passed unanimously in the plenary session of the Conference on 5th October, 2014:

1. The Government of India should pass the Reservation in Promotions to SCs/ STs Bill during the ensuing winter session of Parliament and reservation matters in connection with SCs and STs should be included in the IX Schedule of the Constitution. The Government should take effective and immediate steps to fill up the backlog of vacancies meant for SCs and STs through Special Recruitment Drives.

2. Nowadays, according to the changing global trends in economy, many industries under public sector are shifting to private sectors. As the government provides infrastructural facilities like water, power, rail and roadways, loans, communication, etc., to the private sectors, reservation in employment and promotion to SC and ST candidates in private sectors should be made mandatory.

3. It is a well-known fact that under the Constitution of India, there are three functional organs, viz. judiciary, legislature and executive. But out of 31 judges of the Supreme Court of India, not even a single judge belongs to SC/ST community. Similarly, in 24 High Courts in India, not a single Chief Justice hails from SC/ST community. Out of 906 High Court judges, less than five percent represent SCs & STs which otherwise comprise one-fourth of India's population. Hence, we fervently urge upon the Government of India and the higher judiciary to give adequate representation to SCs and STs in judiciary.

4. We also call upon the Government of India to declare Birth Day of Dr. B.R. Ambedkar as a permanent gazetted holiday in line with other national holidays like Gandhi Jayanti.

5. Almost in all Government departments, SC/ST employees are victimized through anonymous letters with mala fide intentions to hinder their promotions, etc. The Conference condemned casteist attitude of such people, mainly in the Government.

6. It is crystal clear that all over India SC/ST Prevention of Atrocities Act is not being implemented effectively. We therefore urge upon the central Government to issue directions to the States to strictly enforce SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 and SC/ST Special Ordinance 2014. We also urge upon the Government of Tamilnadu to form a State-level Commission for SCs & STs and the Government of India should take steps to give judicial powers to the National Commissions for SCs and STs.

7. As per GO(Ms).92/2013 of the Government of Tamilnadu, admission and tuition fees to be paid by the Government to all SC/ST students who get admissions in private, self-financing engineering, agriculture and medical colleges and deemed universities. Till date disbursement of such fee amounts by the Government of Tamilnadu has not been done. SC/ST engineering, agriculture, medical students are forced to leave such private and self financing colleges and universities. We therefore urge upon the Government of Tamilnadu to disburse fees as per GO.92/2013 immediately, without any further delay.

8. It is shameful for this country that since Independence, no SC/ST candidate could occupy the chair of Cabinet Secretary or Chief Secretary in any State Government. We urge upon the Government of India to abolish the colonial practice of giving extensions in service to retired officials to pave the way for the next generation to higher executive posts.

Need ForFormation Of National Diversity Movement

New Delhi: Bahujan Diversity Mission has launched a nation-wide movement to ensure representation to Scheduled castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) in private sectors. 9th Diversity Day was celebrated at Indian Social Institute. While addressing the delegates from across the country National President of the Mission, Shri H. L. Dusadh, stressed upon the need of formation of a broader alliance small groups working in every state to achieve the goal.

Since Constitutional reservations given by Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar to these communities in government sectors have been shrinking due to rapidly growing privatization, we should force the Union government to introduce a Bill in Parliament to ensure reservation in private sectors. This will not be possible until SC/STs are united at national level.

Dalit Christian leader and columnist R.L. Francis said that globalization has promoted private sectors. The Union government is not keen on creation of jobs in government sectors. Consequently, job opportunity in government is shrinking day by day. In the given situation Dalit-Adivasis have no future if they are not going to confront with the government to implement diversity in private sectors.

Francis also raised the point as to how Churches of India have denied representation to Dalits in church-controlled institutions. He strongly opposed the demand of Dalit Christians to be included in Hindu SC list. He further elaborated that Church is the richest institution having second largest economy after government of India. There are more than 45,000 institutions run by the Churches in India but none of them is willing to give representation to Dalits. He forcefully argued Church must ensure that Dalit representation as well as adopt diversity as soon as possible.

Dr. Mahendra Pratap Rana, activist and thinker, raised the issue of dual slavery carried out by elected representatives in Lok Sabha, State Assemblies and even at lower level. There are 131 MPs in Lok Sabha belonging to SC/ST, out of this figure; SC numbers is 84 and ST 47 respectively. SC and ST candidates are given tickets according to Articles 330 and 332 of the Indian constitution. Therefore, constitutionally, the elected members constitute a separate group. However, they are not recognized as a separate group in the House. SC/ST candidates elected on a symbol of any particular political party are counted the member of that political party.

When it comes to voting in the House, they have to vote on party line despite all disagreements. They are tied with party whip. Defying the whip means losing membership. Whip and party affiliation both is a political gimmick to keep SC/ST elected members divide. This is against the spirit of Articles 330 and 332 of the Indian Constitution. Since they are elected under the special provision (Reservation) of the Indian Constitution. Therefore, party Constitution and party whip should not be binding on them. They should not be controlled by party constitution and party whip. The dual slavery of SC and ST elected candidates will not end till they are not liberated from party line and party whip. SC and ST elected members of Lok Sabha and Assemblies should be recognized as a separate group and must be allotted seats at one place.

Dr. Udit Raj, M.P. Lok Sabha and Chief Guest endorsed the proposal of formation of a national level organization and assured to extend all possible support. Vijayendra Kumar Singh, Editor-Dainik Swaraj Newspaper said that Dalits have been pushed behind socially, educationally and economically. Justice can be accorded to them only when diversity is implemented in India. Mr. Sudesh Tanwar called entire Dalit community to get united if they really want their due share and this could be achieved only through diversity. Prof. (Ms.) Hemlata Mahiswar, Sheel Bodhi and many others share their views and supported the resolution moved at the end of the programme.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn